

आदिवासी एक्सप्रेस

आमजन का एक मात्र हिंदी दैनिक अखबार

फ्रीप्रे

'अदाएं तेरी' में नोरा फतेही और ईशान खट्टर ने मधया धमाल! दर्शक उनकी ऑन-स्ट्रीन अदाओं के हुए दीवाने

झारखंड

उपायुक्त एवं पुलिस अधीक्षक ने की नीट परीक्षा के सफल आयोजन को लेकर बैठक किए

हण्डीबाग

विभावि में आयोजित हुआ एक देश-एक चुनाव विषयक गोष्ठी, बौतर मुख्य अतिथि शामिल हुए सांसद मनीष जायसवाल

झारखंड में वकीलों की हो गई बल्ले-बल्ले: फायदा देने वाला पहला राज्य बना

राजनीतिक संवाददाता द्वारा

रांची: झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शनिवार को राज्य के वकीलों को बड़ी सौभाग्य देते हुए उनके लिए मुख्यमंत्री अधिवक्ता स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू की। इस योजना के अंतर्गत लाभार्थी अधिवक्ता और उसके परिवार को 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य कोमा दिया जाएगा। वहीं गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए वह राशि 10 लाख रुपए तक रहेगी। यह योजना निःशुल्क होगी, यानी लाभार्थी अधिवक्ता को बिल्कुल भी प्रीमियम राशि नहीं देना होगा। इस योजना को शुरू करने के साथ ही झारखंड वकीलों को यह सुधार देने वाला देश का पहला राज्य बन गया है।

योजना के बारे में बताते हुए अधिकारियों ने कहा कि यह देश में ऐसी पहली योजना, जिसमें अधिवक्ताओं को इस तरह के स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ दिया जा रहा है।

योजना के लाभार्थी को शुरुआत के मैके पर बोलते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा, आज इस कार्यक्रम के जरिए मैं करना चाहता हूं कि सरकार की चित्ताएं राज्य के दूर बर्ग के लिए हैं। हमने हमेशा कोशिश की है कि सरकार की आवाज और सरकार की योजनाएं सभी तक पहुंचें। झारखण्ड, देश का सभी स्तरों पर यह बदलाव दिया जाएगा।

योजना का पालन-पालन करने वाला देश का

गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए वह राज्य का

राजनीतिक संवाददाता द्वारा

गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए वह राज्य का

राजनीतिक संवाददाता द्वारा

गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए वह राज्य का

राजनीतिक संवाददाता द्वारा

गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए वह राज्य का

राजनीतिक संवाददाता द्वारा

गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए वह राज्य का

राजनीतिक संवाददाता द्वारा

गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए वह राज्य का

राजनीतिक संवाददाता द्वारा

गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए वह राज्य का

राजनीतिक संवाददाता द्वारा

गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए वह राज्य का

राजनीतिक संवाददाता द्वारा

गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए वह राज्य का

राजनीतिक संवाददाता द्वारा

गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए वह राज्य का

राजनीतिक संवाददाता द्वारा

गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए वह राज्य का

राजनीतिक संवाददाता द्वारा

गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए वह राज्य का

राजनीतिक संवाददाता द्वारा

गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए वह राज्य का

राजनीतिक संवाददाता द्वारा

गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए वह राज्य का

राजनीतिक संवाददाता द्वारा

गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए वह राज्य का

राजनीतिक संवाददाता द्वारा

गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए वह राज्य का

राजनीतिक संवाददाता द्वारा

गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए वह राज्य का

राजनीतिक संवाददाता द्वारा

गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए वह राज्य का

राजनीतिक संवाददाता द्वारा

गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए वह राज्य का

राजनीतिक संवाददाता द्वारा

गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए वह राज्य का

राजनीतिक संवाददाता द्वारा

गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए वह राज्य का

राजनीतिक संवाददाता द्वारा

गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए वह राज्य का

राजनीतिक संवाददाता द्वारा

गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए वह राज्य का

राजनीतिक संवाददाता द्वारा

गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए वह राज्य का

राजनीतिक संवाददाता द्वारा

गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए वह राज्य का

राजनीतिक संवाददाता द्वारा

गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए वह राज्य का

राजनीतिक संवाददाता द्वारा

गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए वह राज्य का

राजनीतिक संवाददाता द्वारा

गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए वह राज्य का

राजनीतिक संवाददाता द्वारा

गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए वह राज्य का

राजनीतिक संवाददाता द्वारा

गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए वह राज्य का

राजनीतिक संवाददाता द्वारा

गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए वह राज्य का

राजनीतिक संवाददाता द्वारा

गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए वह राज्य का

राजनीतिक संवाददाता द्वारा

गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए वह राज्य का

राजनीतिक संवाददाता द्वारा

गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए वह राज्य का

राजनीतिक संवाददाता द्वारा

गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए वह राज्य का

राजनीतिक संवाददाता द्वारा

गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए वह राज्य का

राजनीतिक संवाददाता द्वारा

गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए वह राज्य का

राजनीतिक संवाददाता द्वारा

गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए वह राज्य का

राजनीतिक संवाददाता द्वारा

गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए वह राज्य का

राजनीतिक संवाददाता द्वारा

गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए वह राज्य का

राजनीतिक संवाददाता द्वारा

गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए वह राज्य का

राजनीतिक संवाददाता द्वारा

गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए वह राज्य का

राजनीतिक संवाददाता द्वारा

गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए वह राज्य का

राजनीतिक संवाददाता द्वारा

गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए वह राज्य का

राजनीतिक संव

करेल में भाजपा की ईसाई-पहुंच योजना को लगा झटका

>> **विचार**

“ भाजपा सरकार देश में अल्पसंख्यकों को संविधान द्वारा दी गयी गारंटी और सुरक्षा को कमजोर कर रही है। चर्च द्वारा संचालित दीपिका ने संपादकीय में कहा कि हालांकि आरएसएस ने लेख वापस ले लिए हैं, लेकिन ऑर्गनाइजर ने अभी तक यह स्वीकार नहीं किया है कि उसके द्वारा प्रकाशित जानकारी गलत है। यह केवल उन लेखों के बारे में नहीं है जिन्हें आरएसएस ने वापस ले लिया है या अस्वीकार कर दिया है। यह जिन विचारों को आगे बढ़ाता है और जो कार्य करता रहता है, वे देश में अल्पसंख्यकों, जिनमें ईसाई भी शामिल हैं, की समान नागरिकता की भावना के लिए हानिकारक है। लेख में उत्तरी भारत में ईसाइयों पर चल रहे हमलों को भी उजागर किया।

पी. श्रीकुमारन
ईसाई परिवार अब इस बात से नाराज हैं कि भाजपा और केंद्र सरकार ने उन्हें धोखा दिया है। मानो यह काफी नहीं था, आरएसएस ने अपने मुख्यपत्रों ऑर्गनाइजर में ईसाई समुदाय और चर्च को निशाना बनाते हुए लगातार दो लेख प्रकाशित करके आग में घी डालने का काम किया। संक्षिप्त हीमूँन खत्म हो गया और भाजपा-आरएसएस गठबंधन की राजनीतिक चालाकी ने ईसाई समुदाय के गुरसे को फिर से भड़का दिया। केरल में भाजपा के बहुचर्चित ईसाई-पहुंच कार्यक्रम को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) द्वारा किये गये आत्मघाती गोल के कारण गहरा झटका लगा है, विध्यि संसद द्वारा वक्फ (संशोधन) विधेयक पारित किये जाने के बाद, भाजपा को केरल में ईसाई समुदाय में सेंध लगाने में थोड़ी सफलता मिली थी। वास्तव में, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष राजीव चंद्रशेखर का एनाकुलम जिले के मुनंबम में ईसाई समुदाय के एक वर्ग द्वारा गर्मजोशी से स्वागत किया गया। भाजपा और केंद्रीय मंत्री किरणरिजिजु ने मुनंबम में 600 से अधिक ईसाई परिवारों के बीच उमीद जगायी थी, जो केरल वक्फ बोर्ड (केंडल्यूबी) के साथ कानूनी लड़ाई में उलझे हुए हैं। बोर्ड ने इस आधार पर उनकी संपत्ति पर दावा किया है कि यह संपत्ति उसकी है। केंद्रीय मंत्री ने ईसाई परिवारों का पक्ष लेने के लिए मुनंबम का दौरा भी किया। भाजपा ने शुरू में यह दावा करके उनकी उमीदें जगायी थीं कि विधेयक के कानून बन जाने पर इसका पूर्वव्यापी प्रभाव पड़ेगा और इससे उन्हें लाभ होगा। वास्तव में, भाजपा केरल कैथोलिक बिशप काउंसिल (केसीबीसी) को इसी आधार पर वक्फ (संशोधन) विधेयक का समर्थन करने के लिए राजी करने में सफल रही थी। लेकिन मुनंबम के ईसाइयों को, हालांकि थोड़ी देर से ही सही, यह एहसास हो गया है कि कानून से उन्हें कोई लाभ नहीं होगा। रिजिजु ने खुद स्पष्ट रूप से स्वीकार किया कि कानून से मुनंबम के निवासियों को केंडल्यूबी के साथ उनकी कानूनी लड़ाई में मदद मिलेगी। ईसाई परिवार अब इस बात से नाराज हैं कि भाजपा और केंद्र सरकार ने उन्हें धोखा दिया है। मानो यह काफी



नहीं था, आरएसएस ने अपने मुख्यपत्र ऑर्गनाइजर में ईसाई समुदाय और चर्च को निशाना बनाते हुए लगारार दो लेख प्रकाशित करके आग में घी डालने का काम किया। संश्किप्त हनीमून खत्म हो गया और भाजपा-आरएसएस गठबंधन की राजनीतिक चालाकी ने ईसाई समुदाय के गुरुसे को फिर से भड़ा किया। संसद में वर्क (संशोधन) विधेयक पारित होने के तुरंत बाद, लेखों के प्रकाशन का समाप्त महत्वपूर्ण है, जिसे उनके द्वारा किये गये होगामे के बाद वापस ले लिया गया है। लेकिन नुकसान हो चुका है। केसीबीसी के अधिकारिक प्रवालित फादर थॉमस थाराविल ने स्वीकार किया कि लेखों के प्रकाशन का समय निश्चित रूप से चिंता का विषय है। लेख में दावा किया गया था कि भारत में केंद्रीय चर्च के स्वामित्व वाली भूमि देश में वर्क संपत्तियों से कहीं अधिक है। लेख में यह भी कहा गया था कि ब्रिटिश शासकों ने चर्च को लगभग सात करोड़ हेक्टेयर भूमि पृष्ठे पर दर्दी, और बताया कि 1965 का एक नियम अर्थमें तक लागू नहीं हुआ है, जो औपनिवेशिक युग

के चार्टर, वसीयत, पटु और किराये के समझौते को निर्थक बनाता है। संदेश द्वारा पारित विधेयक केंद्र सरकार को शैक्षणिक और धर्मार्थ उद्देश्य के लिए मुस्लिम धार्मिक बंदोबस्तु विनियमित करने का अधिकार देता है। वेश्वर सवैच्च न्यायालय के हस्तक्षेप ने सरकार व कानून के तत्काल कार्यान्वयन के साथ आ बढ़ने से रोक दिया है। सुप्रीम कोर्ट 5 मई इस मुद्दे पर सुनवाई फिर से शुरू करेगा। विपक्ष दलों ने चर्च की संपत्तियों पर नियंत्रण करने के द्वारा केंद्र सरकार के कदम की कड़ी निंदा की है। उनका कहना है कि मुसलमानों के बाद, योगी सरकार अब अपने अल्पसंख्यक विरोधी एजंसी के तहत ईसायों को निशाना बना रही है। केरल के मुख्यमंत्री पिनाराईविजयन, लोकसभा विपक्ष के नेता शहुल गंधी, केरल में विपक्ष नेता वीडीसीसीशन और केरल प्रदेश कांग्रेस कमेटी (कोपीसीसी) ने कहा कि लेख भाजपा आरएसएस के असली इरादों को उजागर कर रहे हैं, और वह है अल्पसंख्यकों को परेशन करना विजयन ने अल्पसंख्यक समूहों को एक-ए

करके निशाना बनाने और उन्हें चरणबद्ध तरीके से नष्ट करने की एक बड़ी योजना देखी। भाजपा सरकार देश में अल्पसंख्यकों को संविधान द्वारा दी गयी गारंटी और सुरक्षा को कमजोर कर रही है। चर्च द्वारा संचालित दीपिका ने संपादकीय में कहा कि हालांकि आरएसएस ने लेख खापस ले लिए हैं, लेकिन ऑर्गानाइजर ने अभी तक यह स्वीकार नहीं किया है कि उसके द्वारा प्रकाशित जानकारी गलत है। यह केवल उन लेखों के बारे में नहीं है जिन्हें आरएसएस ने खापस ले लिया है या अस्वीकार कर दिया है। यह जिन विचारों को अगे बढ़ाता है और जो कार्य करता रहता है, वे देश में अल्पसंख्यकों, जिनमें ईसाई भी शामिल हैं, की समान नागरिकता की भावना के लिए हानिकारक हैं। लेख में उत्तरी भारत में ईसाइयों पर चल रहे हमलों को भी उजागर किया गया है, साथ ही केंद्र सरकार की चुप्पी की भी आलोचना की गयी है, जो ईसाई समुदाय के खिलाफ हिंसा करने वालों को बढ़ावा दे रही है। इसके अलावा, इंडिया करंट्स, जोउत्तरी भारत के

क्रिस्ट ज्योति प्रांत के कैपुचिन्स के संरक्षण में प्रकाशित एक प्रकाशन है, और जो एक धार्मिक मण्डली तथा चर्च के बढ़ते डर को प्रतिध्वनित करती है, के संपादकीय में कहा गया कि कई समूह, यहां तक कि कुछ जिन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, इसे जीत के रूप में मना रहे हैं। लेकिन क्या यह वास्तव में जीत है, या केवल एक दुःस्वप्न की प्रयोगात्मक शुरुआत है। इस सबका एक संचायी प्रभाव यह हुआ है कि राज्य में ईसाई वोट बैंक में अधिक से अधिक पैठ बनाने के भाजपा के श्रमसाध्य प्रयासों को बड़ी बाधाओं का समाना करना पड़ा है। फिर इसमें आश्र्य की बात नहीं कि सीपीआई (एम) के नेतृत्व वाले वाम लोकतांत्रिक मोर्चे (एलटीएफ) और कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फंट (यूडीएफ) इस मुद्दे पर भाजपा की तीव्र बेचैनी से खुश हैं। दोनों को यकीन है कि ईसाइयों का वह वर्ग जो भाजपा के जाल में फंस गया था, अब अपने कदम पाठें खींच लेगा, वर्तोंकि भगवा पार्टी की धोखाधड़ी उजागर हो गयी है।

सपादकाय

शहीदों का अपमान

शहीदों का अपमान

पहलगाम आतका हमले आर उसम जान गवान वाला क परिजनों का दुख समूदा देश महसूस कर रहा है और आतंकियों के खिलाफ सबमें आक्रेश है। सभी यहीं चाहते हैं कि आतंकवादियों और उन्हें संरक्षण देने वालों के विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई हो। मगर व्यापक स्तर पर ऐसी भावनाएं अगर अनियंत्रित होने लगे और उसकी मार ऐसे लोगों पर पड़ने लगे, जिनका आतंकवाद से कोई लेना-देना न हो, तो वाजिब दुख और आक्रेश की दिशा भटक जाना स्वाभाविक है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद आक्रोश के नतीजे में एक अफसोसनाक प्रतिक्रिया यह देखी गई कि कई जगहों पर बिना किसी वजह के मुसलिम पहचान वाले लोगों को उनका नाम पूछ कर निशाना बनाया गया, उनके साथ मार-पीट गई या उनके व्यवसाय को नुकसान पहुंचाया गया। यह न केवल भावुकता के दिशानीं हो जाने का सबूत, बल्कि देश की कानून-व्यवस्था के सामने एक गंभीर घुनौती भी है। सवाल है कि क्या इस तरह की प्रतिक्रिया देश की लोकतांत्रिक परंपरा के सामने घुनौती नहीं खड़ी कर रही है। पहलगाम हमले में जान गंवाने वाले लेपिट्नेट विनय नरवाल की पती ने अपने पति के लिए न्याय और आतंकियों के लिए सजा सुनिश्चित करने की मांग जरूर की है, लेकिन उन्होंने सिर्फ आक्रोश की वजह से निर्दीश लोगों को निशाना बनाने और नफरत भरे बयान देने की प्रवृत्ति पर अपनी आपत्ति जाहिर की। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में लोगों से सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने व मुसलमानों या कर्मीयों को निशाना न बनाने तथा सिर्फ शांति की आपील की। अपने ऊपर दुख का पहाड़ टूटने के बावजूद उन्होंने जिस तरह अपनी संवेदना और अपने धैर्य को संतुलित बनाए रखा, वह मानवीय मूल्यों के प्रति उनकी आस्था को दर्शाती है। जम्मू-कश्मीर में पिछले कई दशक से आतंकवादियों ने जो किया है, उसका मुकम्मल और ठेस हल निकालने की जरूरत है, याहे इसके लिए कानूनी दायरे में हर स्तर पर सख्ती बरतनी पड़े। मगर आतंकियों की हरकतों की प्रतिक्रिया में अगर कुछ लोग उत्तेजना में निर्दीश नागरिकों के खिलाफ अराजक होने लगें, तो यह न केवल मानवीय संवेदनाओं और मूल्यों के विपरीत होगा! ऐसे लोग शहीदों का अपमान कर रहे हैं।

शरद शर्मा

अमरीकन जर्नल ऑफ प्रिवेटिव मेडिसिन में प्रकाशित ताजा शोध रिपोर्ट ने फिर चेताया है कि अल्ट्रा-प्रोसेस्ट फूड्स का ज्यादा समय तक सेवन करना जानलेवा सबित हो सकता है। ब्राजील यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों की यह रिपोर्ट सचमुच चौकाने वाली है। अमरीका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया समेत आठ देशों में करीब ढाई लाख लोगों पर किए गए शोध में पाया गया कि जहाँ ऐसे खाद्य पदार्थों का कम उपयोग था वहाँ जीवन की गुणवत्ता और आयु बेहतर पाई गई। जबकि अल्ट्रा-प्रोसेस्ट खाद्य सामग्री न केवल हमारे पाचन तंत्र को प्रभावित करती है, बल्कि मोटापा, हृदय रोग, माझपेट और गर्भ तक तिंग प्रभावित करती है।

पारंपरिक

ताजाव जैसी समस्याओं को भी जन्म देती है। अल्ट्रा-प्रोसेस्ट फूड का जिस तरह से पूरे विश्व में प्रचार-प्रसार हुआ है, उससे वह आर्थिक विकास के केंद्र में भी शामिल हो गया है। इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च 2011 में अल्ट्रा-प्रोसेस्ट फूड का बाजार 723 करोड़ रुपए था, जो कि दस साल में यानी वर्ष 2021 में 2535 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। पिछले तीतीय वर्ष तक हास्पिटी उपकरण 6000 करोड़ रुपए की पार

ज्ञात जनगणना के लिए मजबूर हुई मादा सरकार !
मकल सरल इस्तेमाल किया है। अक्षिनी वैष्णव जो आरोप विपक्ष पर रेवंत रेड़ी ने जाति आधारित सर्वेक्षण (समग्र सामाजिक है। सामाजिक न्याय जदिबाद!" उन्होंने अपने पिता और

मोदी सरकार ने आगामी आम जनगणना के साथ जाति जनगणना करने का ऐलान कर दिया है। सरकार इसे अपनी एक उपलब्धि की तरह पेश कर रही है, लेकिन इसे वास्तव में विषयकी ही जीत माना जा रहा है। जाति जनगणना की मांग बेहद पुरानी है और विषय खासकर राहुल गांधी पिछले कुछ सालों से इसको लेकर सरकार पर लगातार दबाव बनाए हुए थे, लेकिन इस घोषणा की टाइमिंग ने सबको चौंका ज़रूर दिया है, क्योंकि इस समय जब पहलगाम हमले को लेकर कार्रवाई की बात कही जा रही थी और पूरा गोड़ी/कॉर्पोरेट मॉडिया युद्ध का माहौल बना ए हुए था, उस समय लगातार हो रही हाई लेवल मीटिंग के बाद अचानक जाति जनगणना का ऐलान किसी को समझ में नहीं आया। यही बजह है कि इसे पहलगाम मुद्दे से ध्यान हटाने और बिहार चुनाव के संदर्भ में देखा-समझा जा रहा है। बुधवार, 30 अप्रैल की शाम के द्विय मंत्री अश्विनी वैष्णव अचानक मॉडिया के सामने आते हैं और घोषणा करते हैं कि केंद्र सरकार आगामी राष्ट्रीय जनगणना में जाति आधारित गणना को शामिल करेगी। यह निर्णय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की राजनीतिक मामलों की समिति (सीसीपीए) की बैठक में लिया गया। यह एक तरीके से मोदी सरकार का यू-टर्न है। सरकारी प्रवक्ता और मॉडिया भले ही इसे मोदी जी का एक और मास्टर स्ट्रोक बताए और कहे कि मोदी जी ने विषय से उसका बड़ा मुद्दा छीन लिया, लेकिन हकीकत यही है कि मोदी सरकार, विषय का एंजेंडा अपनाने पर ही मजबूर हुई है। अब बीजेपी समेत एनडीए के सभी दल इस फैसले का स्वागत कर रहे हैं। लेकिन जाति जनगणना के मुद्दे पर बीजेपी और मोदी सरकार ने कभी अपना रुख़ साफ़ नहीं किया और हमेशा लगभग इंकार की मुद्रा में रही है। सरकार के कई मंत्री और बीजेपी नेताओं ने सार्वजनिक रूप से जाति जनगणना का विरोध भी किया है और ऐसी मांग करने वालों को हिंदू विरोधी और हिंदू धर्म तोड़ने की साज़िश के तौर पर प्रचारित किया। अब यह वीडियो सोशल मॉडिया पर खूब वायरल हैं। यही नहीं, पहलगाम आतंकी हमले के बाद भी बीजेपी की जो पहली पोस्ट सामने आती ही उसमें भी यही लिखा गया था कि धर्म पूछा, जाति नहीं। इसे बीजेपी छत्तीसगढ़ के सोशल हैंडल से जारी किया गया था। लेकिन अब अचानक मोदी सरकार का रुख़ बदल गया है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि जाति आधारित जनगणना से समाज के अर्थात् और सामाजिक सशक्तिकरण में मदद मिलेगी और देश की प्रगति सुनिश्चित होगी। उन्होंने कहा कि कुछ राज्यों द्वारा कराए गए जातिगत सर्वेक्षण राजनीतिक उद्देश्यों से प्रेरित और अपारदर्शी थे, जिससे समाज में संदेह की विस्तृति उत्पन्न हुई। अब केंद्र सरकार ने निर्णय लिया है कि जातिगत जानकारी को सर्वेक्षण के बजाय मुख्य जनगणना के माध्यम से एकत्र किया जाएगा, जिससे पारदर्शित बनी रहेगी। उन्होंने इस निर्णय का बचाव करते हुए कांग्रेस और उसके इंडिया गठबंधन पर आरोप लगाया कि उन्होंने जातिगत जनगणना को हमेशा राजनीतिक लाभ के लिए लगातार चुनाव से जीत करने का बिहार चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है, जो इसी साल नवंबर-दिसंबर में होने हैं। लेकिन वहाँ भी एक पेच है कि बिहार में नीतीश सरकार जाति जनगणना करें या जाति सर्वे करा चुकी है और वहाँ इससे आगे की मांग यानी जाति के आंकड़ों के अनुसार नई विकास योजनाओं और आरक्षण की सीमा 65 फीसद तक बढ़ाने की मांग की जा रही है - यानी वहाँ अब केवल जाति जनगणना मुद्दा नहीं है, बल्कि इससे आगे के क्रियान्वयन का मुद्दा है। इसलिए इससे बिहार में बीजेपी या नीतीश की गठबंधन सरकार को क्या फ़ायदा मिलेगा वह भी एक सवाल है। बिहार की राजनीति के जानकारों का भी यही कहना है कि इस दांव से बीजेपी नीतीश बाबू की बची-खुची ज़मीन भी खिसकाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि यहाँ जाति गणना कराने का श्रेय नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की महागठबंधन सरकार को है। बिहार में जाति आधारित सर्वेक्षण 2023 में कराया गया था। इस दौरान बिहार में महागठबंधन यानी नीतीश कुमार के नेतृत्व में जनाना दल (यूनाइटेड), राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस और वाम दलों की गठबंधन सरकार सत्ता में थी। बिहार में यह ऐसा मुद्दा था कि बीजेपी को न चाहते हुए भी मजबूरी में समर्थन करना पड़ा था। इसलिए माना जा रहा है कि अब इसके जरिये यह दिखाने की कोशिश की जा रही है कि हम पुरे देश में जाति जनगणना कराने जा रहे हैं यानी पिछड़ों के सामाजिक आधार में बीजेपी की सेंध लगाने की यह एक और कोशिश है और इसके जरिये नीतीश बाबू को अगले चुनाव में सियासी तौर पर 'निपटने' की भी कोशिश है। कब होगी यह जनगणना: हमारे देश में हर दस साल में आम जनगणना का नियम है। आखिरी जनगणना 2011 में हुई थी। इस हिसाब से अगली जनगणना 2021 में पूरी हो जानी थी, लेकिन कोविड-19 महामारी के नाम पर इसे स्थगित कर दिया गया और इतना टाला गया कि अभी 2025 में भी इसका काम शुरू नहीं हो पाया है। अब सरकार ने इसमें जाति जनगणना भी जोड़ा है, तो लगता है कि इसमें और दें देंगी, क्योंकि जनगणना फॉर्म को शायद अपडेट करने की तैयारी में है, लेकिन सटीक समय सीमा की घोषणा अभी नहीं की गई है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने यही सवाल उठाया है और एक समय सीमा तय करते हुए इससे आगे का भी रोड मैप मांगा है। सरकार की घोषणा के बाद राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें कहा कि यह हमारा विजन था, जिसे सरकार ने एडाप्ट किया है, हम इसका स्वागत और समर्थन करते हैं। लेकिन साथ ही उन्होंने कहा कि यह पहला कदम है। अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल ने जाति जनगणना के तेलंगाना मॉडल का भी ज़िक्र किया और उसका केंद्रात्मक लोकतांत्रिक अंदोलन का पहला चरण है और भाजपा की नकारात्मक राजनीति का अंतिम। भाजपा की प्रभुत्ववादी सोच का अंत होकर ही रहेगा। संविधान के आंग मनविधान लंबे समय तक चल भी नहीं सकता है। ये इंडिया की जीत है। अरजेंडी नेता और बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने भी इसे उनकी वैचारिक जीत बताया है उन्होंने 'एक्स' पर लिखा "हमारी वैचारिक जीत, सामाजिक न्याय की हमारी लड़ाई अब अगले पड़ाव पर। जो आज हम करते हैं वो बाकी 35-40 साल बाद सोचते हैं। अब हम पिछड़ों/अतिपिछड़ों के लिए विधानसभा, विधानपरिषद, लोकसभा और राज्यसभा में सीटें आरक्षित करेंगे। मंडल कमीशन की अनेक सिफारिशें भी अभी लाग होना शेष

पारंपरिक खाद्य पदार्थों को बढ़ावा देने की जरूरत



2024-25 के अनुसार भारत में चीनी, नमक और असंतुप्त वसा से भरपूर और पोषक तत्वों की कमी वाले अल्ट्रा-प्रोसेसर्ड खाद्य पदार्थों (यूपीएफ) की बढ़ती खपत कई पुरानी बीमारियों और यहाँ तक कि मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं को जन्म दे रही है। भारतीय परिषेक्ष्य को देखें तो भी स्वस्थ भारत की कल्पना तभी साकार हो सकती है जब हम अपने खानपान की प्राथमिकताओं को पुनः परिभाषित करें और स्वाद से अधिक स्वास्थ्य को महत्व दें। आगे चीनी, नमक, शर्की-चीनी-वाइट-शर्की और कॉर्न फैलोज एवं गोबटा जैविक विधियों का उपयोग करके इन विषयों को नियंत्रित करने की जरूरत है।

भी चिंताजनक है। खास तौर से युवाओं के बीच इन फूट-इस को लेकर क्रेज इस कदर है कि इनके बिना दिन की शुरुआत और अंत ही अधूरा लगता है। स्वाद और सुविधा के इस जाल में फंसकर हम पारंपरिक, पौष्टिक और स्वदेशी भोजन से दूर होते जा रहे हैं। ऐसे में समय की मांग है कि सरकारें अल्ट्रा-प्रोसेस्ट फूड पर नियंत्रण के लिए ठोस नीति बनाएं। मिलेट्स और पारंपरिक खाद्य पदार्थों को बढ़ावा देने के लिए जागरूकता अभियान चलाए जाएं। स्कूलों, कॉलेजों और कार्यस्थलों पर हेल्पी फूड को प्रोत्साहित किया जाए। साथ ही, चरणबद्ध तरीके से ऐसे खाद्य पदार्थों के उपयोग की सीमित क्षमता नीति लिया में कार्य हो।

'अदाएं तेरी' में

नोए पतेही

और ईशान खट्टर ने मचाया धमाल! दर्थक
उनकी ऑन-स्क्रीन अदाओं के हुए

दीवाने



रोमांटिक कॉमेडी सीरीज, द रॉयल्स ने अभी-अभी अपना शानदार ट्रैक 'अदाएं तेरी' रिलीज किया है और यह इंटरनेट पर धूम मचा रहा है। ग्लोबल स्टार नोए फतेही और हर दिल अज़ाज़ ईशान खट्टर के साथ यह शानदार गाना रोमांस, रिदम और शाही आकर्षण का एक बेहतरीन मिश्रण है। एक भव्य महल की पृष्ठभूमि पर, फिल्माया गया यह वीडियो एक विजुअल ट्रीट है, जो फिल्म की थीम की भव्यता से मेल खाता है। नोए फतेही ने लाल रंग की बोल्ड ड्रेस में स्क्रीन पर ग्लैमर का तड़का लगाया है और उन्होंने इसे इतनी खूबसूरती से केरी किया है कि हर कदम, हर मोड़ एक राजसी पल जैसा लगता है।

गाने को लेकर दर्शकों की प्रतिक्रियाएं ज़बरदस्त हैं। सोशल मीडिया पर लोग इस जोड़ी की तारीफ करते नहीं थक रहे, जो इस जोड़ी और उनकी शानदार केमिस्ट्री से मोहित हैं। एक यूज़र ने लिखा: 'ओएमजी ये जोड़ी तो लाजवाब है ईशान और नोए साथ में कमाल लग रहे हैं, ये पूरा रोयल फ्लील दे रहा है।'

दूसरे ने कहा: 'नोए ने तो आग लगा दी! कोरियोग्राफी और लुक्स दोनों टॉप क्लास हैं। अब तो द रॉयल्स देखने का इंतजार नहीं हो रहा।' एक फैन ने तो उन्हें ताज भी पहनाया: 'नोए इस म्यूजिक वीडियो में इतनी रॉयल और खूबसूरत लग रही हैं कि सच में यूनिवर्स की ब्रीन लगती हैं।'

वर्ष: 13 | अंक: 3 | माह: अप्रैल 2025 | मूल्य: 50 रु.

समाज दृष्टिकोण

(राजनीति एवं युवा उत्कर्ष की मासिक गाथा)



बिहार चुनाव : क्या एक और नंदल लहर आने को है ?



भूतनी ही 'द भूतनी' को ले डूबेगी, सनी सिंह भी बेअसर, संजय दत्त की फिल्म का पिटना तय!



संजय दत्त की हाल ही में रिलीज हुई फिल्म 'द भूतनी' को लेकर शुरुआती प्रतिक्रियाएं मिली-जुली आ रही हैं। जहां कुछ कलाकारों के काम को सराहा जा रहा है, वहीं फिल्म के 2 अहम किरदारों को इसकी कमज़ोर कही बताया जा रहा है। 'द भूतनी' के ये कमज़ोर किरदार इस फिल्म की सफलता पर पानी फेर सकते हैं। आइए जान लेते हैं कि आखिरकार संजय दत्त की फिल्म 'द भूतनी' के दो कमज़ोर किरदार आखिर हैं कौन?

फिल्म में संजय दत्त 'बाबा' यानी 'कृष्ण त्रिपाठी' का किरदार निभा रहे हैं। बाबा एक घोस्ट हैर है। उनका किरदार आपका खूब मनोरंजन करता है। आसिफ खान और निकंज शर्मा ने भी अपने किरदारों को बखूबी निभाया है। श्रेष्ठ तिवारी की बेटी पलक तिवारी ने भी उन्हें मिले हुए माँके का खूब फायदा उठाते हुए बड़े पद्धें पर अपना कमाल दिखाया है। लेकिन फिल्म में 'भूतनी' का प्रमुख किरदार निभा रहीं मौनी रॉय वर्स्कों को कुछ खास प्रभावित नहीं कर पातीं। उनकी एकिंग में कोई वैरायटी नहीं नजर आती। उनका ये किरदार बहुत ज्यादा बनावटी नजर आता है। उनकी वजह से ये फिल्म हँसार कीमेडी की जगह सिफ्फ कॉमेडी फिल्म बनकर रह गई है।

फिल्म को हो सकता है नुकसान

मौनी रॉय के अलावा 'द भूतनी' में सनी सिंह का किरदार भी कुछ खास रहा नहीं जमा पाया है। फिल्म के इमोशनल सीन्स में उनकी एकिंग थोड़ी कमज़ोर लगती है और इस वजह से दर्शक उनके किरदार से कनेक्ट नहीं कर पाते। फिल्म के बाकी कलाकारों ने अपनी भूमिकाओं के साथ न्याय किया है, लेकिन फिल्म के इन दो प्रमुख किरदारों का कमज़ोर प्रदर्शन फिल्म के लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है।

रेड 2 से हैमुकाबला

'द भूतनी' के साथ अजय देवगन की फिल्म 'रेड 2' भी रिलीज हुई है। 'रेड 2' के मुकाबले संजय दत्त की कम स्कॉर्स मिले हैं। 'द भूतनी' के सभी फिल्मों को मौका देना चाहिए। हालांकि संजय के इस अपील के बाद भी फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर्स और थिएटर के मालिकों ने अजय देवगन की रेड 2 को ही ज्यादा स्क्रीन्स देने का फैसला लिया था।

वो एक्टर जो 1 हजार ऑडिशन में हुआ था
रिजेक्ट, 340 करोड़ी फिल्म ने बदली
किस्मत, अब दे डाली 800 करोड़ी पिंकर

दिंदी सिनेमा में आपने संघर्ष से सफलता तक की कहानीय सुनी होंगी। आज हम भी आपको एक ऐसी ही कहानी से रुबरु करा रहे हैं ये कहानी एक ऐसे एक्टर की है, जो आज हिंदी सिनेमा के सबसे बेहतरीन एक्टर्स में से एक माना जाता है, लेकिन कभी ये ऑडिशन के लिए दर-दर भटकता था।

SUGANDH
MASALA TEA
Enriched with Real spices

सुगन्ध
मसाला चाय
Enriched with Real spices

www.sugandhtea.com